(Authoritative English Text of this Department Order No. FFE-B-A(3)-5/2020- dated 4th January, 2025 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

## Government of Himachal Pradesh Department of Forest

23489-558
No. FFE-B-A(3)-5/2020- Dated Shimla, the

4th January, 2025

#### **ORDER**

Whereas, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 4 read with section 7 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978, had issued Order No. FFE-B-A(3)-4/99, dated 10.09.2002 for temporarily regulating, restricting and prohibiting throughout the areas in Himachal Pradesh (Except the areas falling within the limits of Municipal Corporation, Municipal Councils, Nagar Panchayats and Cantonment Boards) as specified in Schedule appended to the said order, the acts specified therein for a period of 30 years from the publication of the said order in Rajpatra, Himachal Pradesh and the said order was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 4<sup>th</sup> October, 2002;

And whereas, vide order No. FFE-B-A(3)-1/2017, dated 8<sup>th</sup> February, 2021, some provisions of para-1 of the above orders were amended;

And whereas, vide Order No. FFE-B-A(3)-5/2020 dated 28<sup>th</sup> August, 2023, further amendments were made in the Order No. FFE-B-A(3)-1/2017, dated 8<sup>th</sup> February, 2021;

And, whereas, the State Government after due inquiry is satisfied that it is necessary and expedient to modify the said orders dated 10-09-2002, 8<sup>th</sup> February, 2021 and 28<sup>th</sup> August, 2023 in the interest of maintenance of ecology, forest and wild life conservation and for preventing the exploitation of farmers;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 4 read with section 7 of the Act *ibid* the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the said orders namely:

#### **AMENDMENTS**

Amendment of Para 1. for Para 1 of the order dated 10<sup>th</sup> September, 2002, the following shall be substituted, namely:-

"1. the cutting of trees or timber and removal thereof in such areas shall be prohibited except for the following species of trees:

Sr.No	. Local Name of Species	<b>Botanical Name of Species</b>
1 2 3.	Safeda Poplar Bamboo culms/ Lathi bans/ Maggar/ Dharainch/ Bans	Eucalyptus species Populus deltoids Dendrocalamusstrictus/ Dendrocalamushamiltonii/ Bambusanutans/Bambusa bambos

Provided that there will be no prohibition or restrictions on the number of trees to be felled for the purpose of bonafide domestic uses of fodder and fuel:

Provided further that the owners may, for their bonafide domestic and agricultural use, fell up to three trees each year without permission. Any felling of more than three trees requires written permission from the competent authority, i.e., the Divisional Forest Officer concerned:

Provided also that trees of Khair shall be felled for sale in accordance with the tenyear felling programme, which may be framed by the officers of the Forest Department and approved by the State Government. The trees shall only be felled after obtaining permission from the following authorities:-

Sr. N	lo. Number of Trees	Competent Authority
1	Upto 200 trees in a year	Divisional Forest Officer
2	Upto 300 trees in a year	Chief Conservator/Conservator of Forests
3	Upto 400 trees in a year	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF).
4	Above 400 trees in a year	Himachai Pradesh Government.

Note: The felling of trees for sale in respect of other species shall be permitted by the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), provided that the process of demarcation/marking of trees was completed under the ten-year felling programme before the issuance of the said amended order of 2025.

Provided also that any person felling trees, either for domestic, agricultural use, or for sale, shall be required to plant at least three trees for each tree felled. If a fruit orchard is planted in such areas, it shall be done according to the norms laid down by the Horticulture Department of Himachal Pradesh for the complete stocking of the area;

By Order,

Kamlesh Kumar Pant, IAS Addl. Chief Secretary (Forest) to the Government of Himachal

#### Endst. No. As above Dated Shimla-2 the

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. All the Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
- 2. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
- 3. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
- 4. The Principal Chief Conservator of Forests, (HoFF) HP Shimla-1.
- 5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) HP Shimla-1.
- The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Government of HP, Shimla-02.
- 7. The Joint Secretary (GAD) to the Government of HP, Shimla-02 w.r.t. his letter No. GAD-C(A)9-4/2013 dated 25.12.2024.
- 8. APCCFs (IT), CCFs/DFOs (Territorial & Wildlife).
- The Controller, HP Printing Press, Shimla for publication in H.P., Rajpatra.
- 10. Guard file.

(Vijay Kumar, I.A.S.) Special Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh

Endst.No.Ft.783-54/70 (Mgt.) Orders/Vol. XX

Dated Shimla-1, the

Copy of order (both in English and Hindi) is forwarded to:-

1. All CCFs/CFs (T & WL) in HP for information and further necessary action please.

Addl. Pr.CCF (Forest Management) O/o Pr. CCF (HoFF) Shimla, H.P. head-management@hp.gov.in

Ph. 0177-2624376

# हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

संख्याः एफ०एफ०ई०-बी.-ए(3)-5/2020-

तारीखः शिमला-2,

04 जनवरी, 2025

### आदेश

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू—परिरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश संख्याः एफ0एफ0ई0—बी—ए(3)—4/99, तारीख 10—09—2002 द्वारा हिमाचल प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में (नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और छावनी बोर्डों की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों के सिवाय) उक्त आदेश से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों को उक्त आदेश के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित और प्रतिषिद्ध किया गया था और उक्त आदेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 4 अक्तूबर, 2002 को प्रकाशित किया गया था;

और आदेश संख्या एफ0एफ0ई0-बी.-ए(3)-1/2017, तारीख 08 फरवरी, 2021 के द्वारा उक्त आदेश के पैरा 1 के कुछ उपाबन्धों को संशोधित किया गया था;

और आदेश संख्या एफ०एफ०ई०-बी.-ए(3)-5/2020, तारीख 28 अगस्त, 2023 द्वारा आदेश संख्याः एफ०एफ०ई०-बी-ए(3)-1/2017 तारीख 08 फरवरी, 2021 में और संशोधन किए गए थे;

और राज्य सरकार का सम्यक् रूप से जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पारिस्थितिकी, वन और वन्यजीव संरक्षण के रख-रखाव के हित में और किसानों के शोषण को रोकने के लिए तारीख 10 सितम्बर, 2002, 08 फरवरी, 2021 और 28 अगस्त, 2023 के उक्त आदेशों को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेशों में निम्नलिखित संशोधन करने का सहर्ष आदेश देते हैं, अर्थात् :-

# संशोधन

पैरा-1 का संशोधन।

तारीख 10 सितम्बर, 2002 के आदेश के पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1. वृक्षों की निम्नलिखित प्रजातियों के सिवाय ऐसे क्षेत्रों में या काष्ट्र/लकड़ी का कटान और उनका हटाया जाना प्रतिषिद्ध होगाः

क्रम संख्या	प्रजातियों का स्थानीय नाम	प्रजातियों का वानस्पतिक नाम
1.	सर्फदा	यूकेलिप्टस प्रजाति
.2.	पॉपलर	पॉपलस डेलटियॉडिस

परन्तु यह कि चारे और ईंधन के वास्तविक घरेलू उपयोग के प्रयोजन के लिए काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या पर कोई प्रतिषेध नहीं होगाः

परन्तु यह और कि स्वामी उनके वास्तविक घरेलू और कृषि उपयोग के लिए प्रति वर्ष बिना अनुज्ञा के तीन वृक्ष काट सकेंगे। तीन पेड़ों से अधिक किसी कटान के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी की लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी:

परन्तु यह और भी कि बिकी के लिए खैर के वृक्षों का कटान दस वर्षिय कटान कार्यक्रम के अनुसार होगा जिसे वन विभाग के अधिकारीयों द्वारा तैयार और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। निम्नलिखित से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही वृक्षों का कटान किया जाएगा:-

क0 सं0	वृक्षों की संख्याः	सक्षम अधिकारी
1.	एक वर्ष में 200 वृक्षों तक	वन मण्डल अधिकारी
2.	एक वर्ष में 300 वृक्षों तक	मुख्य अरण्यपाल /
		अरण्यपाल वन
3.	एक वर्ष में 400 वृक्षों तक	प्रधान मुख्य अरण्यपाल
		(वन बल प्रमुख)
4.	एक वर्ष में 400 वृक्षों से अधिक	हि0 प्र0 सरकार।

टिप्पण: बिकय के लिए अन्य प्रजातियों की बाबत वृक्षों के कटान की अनुज्ञा प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) द्वारा प्रदान की जाएगी परन्तु सीमांकन/वृक्षों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया दस वर्षिय कटान कार्यकम के अधीन 2025 के उक्त आदेश से पूर्व पूर्ण हो।

परन्तु यह और कि या तो घरेलू, कृषि उपयोग या विकय के लिए वृक्ष काटने वाले किसी व्यक्ति से ऐसे काटे गए प्रत्येक वृक्ष के बदले में तीन वृक्षों का रोपण अपेक्षित होगा। ऐसे क्षेत्रों में यदि फल उद्यान रोपित किया जाता है तो यह क्षेत्र के पूर्ण स्टाकिंग (स्टाक रखना) के लिए हिमाचल प्रदेश के उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित किए गए सन्नियमों के अनुसार होगा।"।

आदेश हारा,

कमलेश कुमार पंत, भा.प्र.से. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार 23489-558

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि

तारीख शिमला

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 3. समस्त जिला उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
- 4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) हिमाचल प्रदेश शिमला-1।
- प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश शिमला–1।
- 6. अतिo एल.आर.-सह-अतिo सचिव (विधि) हिo प्रo सरकार।
- 7. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0 प्र0 सरकार को उनके पत्र संख्याः जी०ए०डी०—सी०(ए)9—4/2013 दिनांक 25.12.2024 के सन्दर्भ में।
- 8. समस्त अति० वन्य अरण्यपाल (आई.टी.), मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वन मण्डलाधिकारी हि0 प्र0।
- नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।

10. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार, आई.ए.एस.) विशेष सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार

\*\*\*\*